भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-563

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

बिजली खपत प्रणाली को सरल बनाना

563. श्री टी. जी. वेंकटेशः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में बिजली खपत प्रणाली को सरल बनाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विद्युत समवर्ती सूची का एक विषय है। विद्युत का वितरण तथा इस**की** खपत राज्य सरकार/विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्काम) के कार्य क्षेत्र **में** आ**ता** है। तथापि, भारत सरकार विभिन्न नीतियां एवं योजनाएं तैयार करके राज्य सरकारों के प्रयासों की अनुपूर्ति करती है। सरकार ने ऊर्जा संरक्षण तथा मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जिनमें ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब, कृषि संबंधी पंप, पंखे एवं एयर कंडीशनर तथा पीएटी (निष्पादन, उपलब्धि, व्यापार) स्कीम के माध्यम से उद्योग में ऊर्जा दक्षता लाना शामिल है।

भारत सरकार उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** (डीडीयूजीजेवाई) तथा **एकीकृत विद्युत विकास स्कीम** (आईपीडीएस**)** के माध्यम से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता भी कर रही है। इससे देश में विद्युत की खपत में सुधार **लाने में सहायता मिलेगी**।

****